International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED), ISSN: 2320-8708
Vol. 2 Issue 6, Nov.-Dec., 2014, pp: (84-89), Impact Factor: 1.267, Available online at: www.erpublications.com

भारत–नेपाल संबंध

द्वितीय जन आदोंलन के पश्चात् परिवर्तित भू–सामरिक हितों के संदर्भ में

डॉ. पंकज गुप्ता

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान

लघु शोध सारांश

नेपाल, भारत–चीन के मध्य "बफर स्टेट" होने के कारण भारत के लिए सामरिक दृष्टि से सदा महत्वपूर्ण रहा है और दोनों देशों में शताब्दियों पुराने सांस्कृतिक–धार्मिक सम्बन्ध है। भारत द्वारा नेपाल के प्रति "द्विस्तम्भीय नीति" का अनुसरण किया गया जो संवैधानिक राजतन्त्र के अस्तित्व के साथ पूर्ण प्रजातान्त्रिक नेपाल पर बल देती है। किन्तु राजतन्त्र के अंत व लोकतंत्र की स्थापना की वजह से भारतीय वैदेशिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। वैश्वीकरण के दौर में नेपाल आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए बारात पर आश्रित है वहीं दक्षिण एशिया में चीन की प्रभुत्ववादी नीति के मद्देनजर स्थिर नेपाल राष्ट्रीय हितों के लिए प्रथम प्राथमिकता है।

वस्तुतः भारत द्वारा नेपाल में अभ्युदित नवीन प्रतिमानों के अनुरूप अपनी विदेश नीति को सक्रियता एवं गत्यात्मकता प्रदान करनी होगी ताकि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा एवं राजनीतिक स्थिरता विद्यमान रहे और दोनों देशों के सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता आये ।

भारत व नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक कारकों से निर्मित हुई है। जहॉ एक ओर नेपाल, भारत और चीन के मध्य अवरोधक राष्ट्र होने के कारण, भारत के लिए सामरिक दृष्टि से सदैव महत्वपूर्ण रहा हैए वहीं दूसरी तरफ स्थल अवरूद्ध राष्ट्र के रूप में नेपाल की निर्भरता भारत पर बढ़ जाती है। भारत–नेपाल संबंधों की आधारशिला जुलाई, 1950 की शांति व मित्रता की संधि है। आरम्भ में नेपाल का झुकाव भारत की ओर था, किन्तु 1970 के पश्चात् भारत की शक्ति से चिन्तित होकर नेपाल ने **"समदूरी सिद्धांत"** अपनाया, किन्तु 1996 में भारत द्वारा 'गुजराल सिद्धांत' के माध्यम से मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया गया। मुख्यतः भारत द्वारा नेपाल के प्रति **'द्विस्तम्भीय नीति'** अपनाई गई जो संवैधानिक राजतंत्र अस्तित्व के साथ पूर्ण प्रजातांत्रिक नेपाल पर बल देती थी, किन्तु द्वितीय जन आंदोलन (2006) के पश्चात् राजतंत्र के अन्त तथा लोकतंत्र की स्थापना के कारण परिवर्तित परिदृश्य में भारत–नेपाल संबंधों में नवीन प्रतिमानों एवं समीकरणों का प्रादुर्भाव हुआ है।

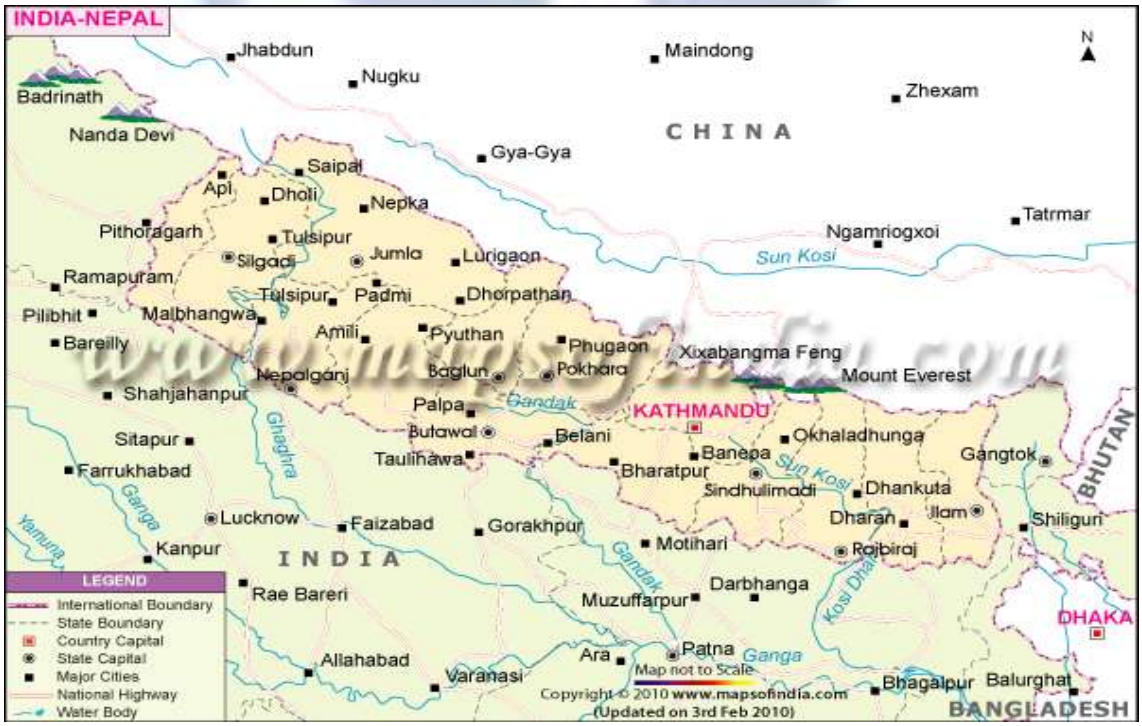

समकालीन परिदृश्य

मई 2008 में राजशाही की समाप्ति की औपचारिक घोषणा के पश्चात् नेपाल को धर्मनिरपेक्ष– लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। नेपाल में 10 अप्रैल, 2008 को संविधान सभा के लिये हुए चुनाव के परिणाम अनपेक्षित और ऐतिहासिक रहे। इन चुनावों में माओवादी सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आये जो वर्षों से राजनीतिक दलों की स्वार्थपरता व सत्ता की लोलुपता से त्रस्त नेपाली जनता का जवाब था।

अगस्त, 2008 में माओवादियों द्वारा प्रचण्ड के नेतृत्व में संविद सरकार का गठन किया गया। इस राजनीतिक परिघटना ने नेपाल की आन्तरिक एवं बाह्य राजनीति में विभाजनकारी प्रवृति को बढ़ावा दिया। माओवादियों द्वारा नेपाल–भारत संधि, 1950 की समाप्ति की मॉग व चीन के प्रति झुकाव द्वारा भारत–नेपाल के मध्य राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से घनिष्ट संबंधों के समक्ष प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की गई । किन्तु नेपाली सेना में 3010 सैनिकों की भर्ती, सेवानिवृत बिग्रेडियर जनरलों की पुनः बहाली तथा राष्ट्रीय खेलों के बहिष्कार संबंधी मुद्दों पर मतभेद के चलते राजनीतिक दलों के मध्य उपजे ध्रुवीकरण के कारण माओवादी प्रधानमंत्री प्रचंड को इस्तीफा देना पड़ा, तत्पश्चात् माधव कुमार के नेतृत्व में 22 दलों की संविदा सरकार अस्तित्व में आयी, जिसे माओवादियों ने भारत की कठपुतली सरकार की संज्ञा दी और आरोप लगाये कि भारत ने उनकी सरकार को गिराया है। माओवादियों ने माधव कुमार की सरकार के समक्ष 'नागरिक सर्वोच्चता' स्थापित करने की मॉग की और इसके लिए पूरे नेपाल में आन्दोलन चलाया। परिणामस्वरूप 30 जून, 2010 को नेपाल के प्रधानमंत्री माधव कुमार ने माओवादियों की मॉग पर राष्ट्रीय आम सहमति से गठित सरकार के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु इस्तीफा दे दिया और कामचलाऊ सरकार का नेतृत्व स्वीकार किया किन्तु नेपाली राजनीतिक दल सर्वसम्मति से सरकार गठित करने में असफल रहे। नेपाल में नये प्रधानमंत्री के चुनाव हेतु लगभग 7 माह से चला आ रहा गतिरोध उस समय समाप्त हो गया जब पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्ससिस्ट (सी.पी.एन.एम.) ने इस पद हेतु कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्ससिस्ट लेनिनिस्ट (सी.पी.एन., यू.एम.एल.) के उम्मीदवार झलनाथ खनाल को समर्थन प्रदान किया किन्तु खनाल के नेतृत्व वाली सरकार में माओवादी शामिल नहीं हुए[1]। नेपाल के प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल ने शांति प्रक्रिया में ठोस प्रगति नहीं कर पाने के कारण 14 अगस्त 2011 को त्यागपत्र दे दिया था किन्तु 28 अगस्त तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। 28 अगस्त, 2011 के चुनाव में माओवादी बाबूराम भट्टाराई ने संविधान सभा में चौथी बड़ी पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट (यू.डी.एम.एफ.) व अन्य छोटी पार्टियों का समर्थन हासिल कर चुनाव में अपनी प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार आर.सी. पौडियाल को पराजित किया व नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने गये[2]। नेपाली जनता की अत्यंत उत्कृष्ट जनभावनओं और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद देश के लिए नवीन संविधान तैयार करने और उसे लागू करने की समय सीमा समाप्त हो जाने कारण अंततः अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने इस संविधान को भंग करते हुए नई संविधान सभा के गठन हेतु चुनावों की तिथि 22 नवम्बर, 2012 निर्धारित की। किन्तु राजनीतिक गतिरोध के चलते चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके। तत्पश्चात् 14 मार्च, 2013 से नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने दूसरी संविधान सभा हेतु 19 नवम्बर, 2013 चुनाव सम्पन्न करवाये। जिसमें नेपाली कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और आश्चर्यजनक रूप से एकीकृत नेपाली साम्यवादी दल (माओवादी) तीसरे स्थान पर आई। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के नेतृत्व वाली नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) दूसरे स्थान पर आई।

तालिका

दल	प्राप्त स्थान	नेतृत्वकर्ता
नेपाली कॉग्रेस	196	सुशील कोइराला
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी)	175	के.पी. शर्मा
नेपाली एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)	80	पुष्प कमल दहल
नेपाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र दल	24	कमल थापा
अन्य	**100**	
कुल	**575**	

10 फरवरी, 2014 को संविधान सभा की बैठक में नेपाली कॉग्रेस के सुशील कोइराला नेपाल के पांचवे प्रधानमंत्री चुने गये। उनकों पक्ष में 405 मत मिले जबकि विपक्ष में 148 मत पड़े। यह स्थिति नेपाली कॉग्रेस व झलनाथ खनाल के नेतृत्व नेपाली साम्यवादी दल (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के मध्य सात सूत्रीय समझौते के पश्चात् ही अस्तित्व में आई है। किन्तु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नेपाल के सभी राजनीतिक दल संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका किस प्रकार निभाते है क्योंकि अतीत को अनुभव कोई ज्यादा सुखद नहीं है। नेपाल में लम्बे समय जारी राजनीति अस्थिरता की वजह से शांति प्रक्रिया बाधित और विकास अवरूद्ध है[4]। इस समय भारत–नेपाल के द्विपक्षीय संबंध सबसे कठिन दौर में हैं, जहॉ एक ओर नेपाल की आन्तरिक

स्थिति अत्यंत विस्फोटक है, वहीं भारत के समक्ष भी नेपाल में बदलते परिदृश्य के मद्देनजर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल प्रभावी नीति के निर्माण की चुनौती है। वर्तमान में नेपाल की राजनीति आन्तरिक व बाह्य राजनीतिक कर्ताओं से अत्यंत प्रभावित है[5]। जिससे बड़े पैमाने पर आन्तरिक उथल–पुथल व अस्थिरता विद्यमान है।

भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियॉ

अप्रैल, 2008 में नेपाल में सम्पन्न हुए संविधान सभा के चुनावों में माओवादियों की ऐतिहासिक विजय के पश्चात् नवीन समीकरणों व आयामों का उद्भव हुआ है । जिसने दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेपाल में भारत की विदेश नीति के समक्ष प्रमुख अवरोधक बिन्दु अग्रलिखित हैं:–

- प्रथम संविधान सभा के चुनावों के पश्चात् सत्तारूढ़ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा भारत–नेपाल संबंधों में कटुता पैदा की गई। माओवादियों द्वारा नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए भारत को नेपाल की सम्प्रभुता के समक्ष सबसे बड़े खतरे के रूप में प्रचारित किया गया। प्रचंड द्वारा भारत–नेपाल संबंधों में पुनः चीन कार्ड खेलना, भारत पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाना, भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की नियुक्ति को औपनिवेशिक बताना तथा नेपाल में जारी अस्थिरता के लिए भारत को दोषी ठहराना इत्यादि ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में दरार उत्पन्न कर दी है। 1950 की शांति एवं मित्रता की संधि को असमान मानते हुए सभी माओवादी प्रधानमंत्रियों द्वारा इसकी पुनर्समीक्षा की मांग उठाई गई तथा इसे नेपाली राष्ट्रवाद के समक्ष सबसे बड़ी बाधा के रूप में प्रचारित किया गया।

- एक सर्वमान्य और सर्वसम्मत संविधान को तैयार करने का दायित्व संविधान सभा को सौंपा गया था। संविधान सभा पर मई, 2010 तक नया संविधान बनाने का दायित्व था। 28 मई, 2012 को चार वर्ष के कार्यकाल में भी संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य पूरा नहीं कर पाई। शांति प्रक्रिया तो पहले ही अधर में लटकी पड़ी है तथा नवीन संविधान निर्माण का कार्य नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य जारी गतिरोध की वजह से बाधित है। नेपाल में वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितता, माओवादियों के गैर लचीलेपन और जिद का परिणाम है। नेपाल अभी इस दौर से गुजर रहा है कि संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था लाने से भी बुनियादी मुद्दों में आशाजनक बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बल्कि बिगाड़ ही दिखाई पड़ रहा है[7]। नेपाल में जारी अस्थिरता से भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- भारत को वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला विषय सुरक्षा से संबंधित है। नेपाल के साथ भारत की 1664 कि.मी. लम्बी खुली सीमा रेखा है जिसका सर्वाधिक दुरूपयोग माओवादी आन्दोलन से पूर्व पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. ;प्ैण्ण्द्ध द्वारा भारत विरोधी कार्यों के लिए किया जाता रहा है। लेकिन नेपाल के नवजात लोकतंत्र के विकास में माओवादियों की प्रमुख भूमिका से भारत को अंदेशा है कि भविष्य में नेपाल के माओवादियों और भारत में विद्रोह कर रहे माओवादियों में संबंध विकसित होने से भारत की आन्तरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

खुली सीमा का दुरूपयोग जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी, मानव व्यापार और हथियारों की तस्करी जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि करमा कग्यू बौद्ध धर्म के मुखिया सत्रहवें करमापा उग्येन त्रिनेल दोरजे के मठ से 6 करोड़ रूपये की भारतीय मुद्रा और चीन समेत दो दर्जन देशों की विदेशी मुद्रा को बरामद किया गया, जो नेपाल के रास्ते लायी गई[8] ।लेकिन इससे बड़ा खतरा आंतकवादियों से है जो दोनों देशों के मध्य खुली सीमा का फायदा उठाकर आतंकी गतिविधियों को सम्पन्न करने हेतु नेपाल के रास्ते भारत प्रवेश करते हैं। दोनों देशों ने इस समस्या की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयास करते हुए 15 जनवरी, 2010 को काठमाण्डू में सहमति–पत्र पर दस्तख़त किये और नेपाल ने इस संदर्भ में आश्वासन दिया कि नेपाली क्षेत्र से भारत विरोधी किसी भी गतिविधि को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी[9]। लेकिन नेपाल के पास ढ़ॉचागत सुरक्षा व्यवस्था का नितान्त अभाव है। खुली सीमा का अपराधियों द्वारा दुरूपयोग भारत व नेपाल के लिए मुख्य चुनौती बना हुआ है।

- नेपाल में माओवादी भारत–नेपाल के मध्य सीमा विवादों का निपटारा चीन की मदद से करना चाहते हैं, विशेषकर कालापानी सीमा विवाद क्षेत्र का। कालापानी क्षेत्र भारत–नेपाल–चीन तीनों देशों की सीमा पर अवस्थित है। यह लगभग 75 कि.मी. का क्षेत्र है जिस पर 1962 में भारत–चीन युद्ध से ही भारतीय चौकी स्थापित है। भारत व नेपाल दोनों ही देश कालापानी को अपना–अपना हिस्सा मानते हैं। यह मुद्दा भी दोनों देशों के मध्य तनाव उत्पन्न करता रहा है।
- नेपाल और चीन के संबंध पंचशील सिद्धांत पर आधारित रहे हैं जिसके अनुसार चीन कभी भी नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नही करेगा। वहीं नेपाल भी चीन की सम्प्रभुता तथा तिब्बत व ताइवान के संदर्भ में क्षेत्रीय एकता का सम्मान करेगा[10]। माओवादियों के सत्ता में आने तथा एशिया में वर्चस्व स्थापित करने की नीति के अनुपालन में चीन ने अब नेपाल की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर नेपाल के प्रति एक सक्रिय नीति प्रारम्भ की है ताकि अन्य बाहरी शक्तियों विशेषकर भारत को, नेपाल के आन्तरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप को रोका जा सके। चीन ने अपने इस कदम से नेपाल में भारत के खिलाफ प्रतिसंतुलनकारी नीति का प्रतिपादन किया है। चीन ने नेपाल में तातोपानी नामक स्थान पर सूखा बन्दरगाह विकसित कर रहा हैए साथ ही आधारभूत संरचना संबंधी अनेक राजमार्गों, पुलों का निर्माण कार्य भी कर रहा है। चीन और भारत के मध्य नेपाल को अपने प्रभाव में लाने की प्रतिस्पर्द्धा है। नेपाल की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए भारत के सामरिक हितों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक भी है की नेपाल की सीमा पर चीन को आने से रोका जाये क्योंकि चीन द्वारा तिब्बत से चीन–नेपाल सीमा तक रेलवे लिंक का विस्तार भारत–नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए सुरक्षा हेतु खतरा है।
- पिछले डेढ़ दशक से जारी आन्तरिक संघर्ष से सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को धक्का पहुँचा है। लेकिन अप्रैल, 2008 के पश्चात् नेपाली व्यवसायियों को यह आशा थी कि लोकतंत्र के आगाज के साथ ही आर्थिक वातावरण में सुधार होगा तथा लगातार हो रही बिजली कटौती, कर्मचारियों और नेताओं की बीच अविराम वेतन विवाद, लगातार होते हमले, कानून व व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, राजमार्गों को रोके जाना, चौथ वसूली की धमकी, कुछ श्रमों संघों द्वारा फैलाये गये आतंक, घटता विदेशी निवेश इत्यादि परिवर्तित होंगी[11]। किन्तु लगातार जारी अस्थिरता ने स्थितियों को और अधिक खराब किया है। जिससे भारत के साथ लगातार व्यापार असंतुलन में वृद्धि होती जा रही है। यह तथ्य अग्रलिखित तालिका से भी स्पष्ट होता है–

तालिका भारत व नेपाल के मध्य द्विपक्षीय व्यापार

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन
2007.08	1507.42	628.56	2135.98	878.86
2008.09	1570.15	496.04	2066.19	1074.11
2009.10	1533.31	452.61	1985.92	1080.70
2010.11	2168.06	513.40	2681.47	1654.66
2011.12	2523.41	427.38	2950.79	2096.02
2011.12 ;अप्रैल–दिसंबरद्ध	1841.54	363.83	2205.38	1477.71
2012.13 ;अप्रैल–दिसंबरद्ध	2006.86	341.18	2348.04	1665.69

(अनंतिम स्त्रोत : DGCIS ½

नेपाल कृषि, पानी–बिजली, आधारभूत ढॉचा व पर्यटन के असीम विकास की संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है। लेकिन उन्हें विकसित करने के लिए राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सहायक श्रम कानून तथा भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढॉचें की आवश्यकता है[12]। नेपाल में जारी अस्थिरता की वजह से बड़ी संख्या में नेपाली युवा खुली सीमा को पार कर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। किन्तु ये बेरोजगार युवा अराज्यकर्ताओं के सशस्त्र समूहों में शामिल होकर भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

सारतः भारत की विदेशी नीति के सम्मुख नेपाल में भारतीय निवेश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा नेपाल के आर्थिक विकास में योगदान देना प्रमुख चुनौती है।

भारतीय विकल्प

नेपाल में पिछले पॉच वर्षों से जारी शांति एवं संविधान निर्माण की प्रकिया के प्रति भारतीय नीति सतर्कता युक्त सहयोग की नीति है लेकिन एशिया में बदलते समीकरणों व संदर्भों के मद्देनज़र भारत को नेपाल में नवजात लोकतंत्र संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 'प्रो एक्टिव कूटनीति' अपनानी होगी ताकि बाहरी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। इस संदर्भ में कतिपय विकल्प अग्रलिखित हैं:–

- भारत–नेपाल संबंधों को बेहतर बनाने हेतु विभिन्न आयामों यथा राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम व सांस्कृतिक आयाम पर विशेष बल दिया गया किन्तु एक महत्वपूर्ण पहलू भू–मनोवैज्ञानिक पर अब तक ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है। जो दोनों देशों के संबंधों की समझ को जानने की अत्यंत मूल्यवान अवधारणा है। भारत को नेपाल के साथ संबंधों में सदैव इस नेपाली मानसिकता को ध्यान में रखना चाहिए कि नेपाल यद्यपि छोटा राष्ट्र है किन्तु फिर भी वे हर स्तर पर स्वयं के लिए बराबर का दर्जा चाहते हैं। नेपाल को भारत से सहायता नहीं अपितु समान रूप से लाभ पहुँचाने वाली योजनाऐं चाहिए। जबकि भारतीय विदेश नीति लम्बे समय तक पणिक्कर के साथ प्राधान्यवादी असमामित संबंध के सिद्धांत पर आधारित थी। अतः भारत व नेपाल के मध्य भू– मनोवैज्ञानिक आयाम के आधार पर विद्यमान गतिरोधों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। इसे विदेश नीति का आधार बनाना चाहिए।
- नेपाल में माओवादियों के सत्ता में आने के पश्चात् चीन के बढते प्रभाव ने भारत के नेपाल में राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक एवं व्यापारिक हितों को गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। चीन द्वारा नेपाल के साथ सुरक्षा संधि की जा रही है जो भारतीय हितों के प्रतिकूल है साथ ही 1950 की संधि का उल्लंधन है। अतः भारत को नेपाल में उभरते नवीन आयामों के अनुसार लघु व दीर्घकालीन नीति विकल्प के रोड़ मैप के साथ कार्य करना होगा। भारत द्वारा चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए नेपाल के साथ आर्थिक संबंधों को अधिक सशक्त बनाने पर बल देना होगा जिसके लिए व्यापार में असंतुलन को कम करने की आवश्यकता है,साथ ही दोनों देशों के मध्य तनाव पैदा करने वाले मुद्दों जैसे विवादास्पद संधियों, अतिक्रमण, भारत द्वारा तराई क्षेत्र में विशेष समूहों को समर्थन देना तथा माओवादियों की सरकार को अस्थिर करना इत्यादि पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है[13]। भारत को इन पर एक स्पष्ट एवं सकारात्मक नीति के अनुसरण की आवश्यकता है।
- अनियमित और खुली सीमा दोनों देशों के लिये प्रमुख चुनौती है। सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के संदर्भ में पूर्व में अपनाई गई नीति की समीक्षा की महती आवश्यकता है जो वर्तमान में जारी राजनीतिक अनिश्चिताओं के चलते आसान नहीं है। फिर भी भारत को सीमा प्रबंधन के तरीकों में सुधार हेतु हर संभव कदम उठाने होंगे, ताकि भारत के विरूध क्रियाकलापों में लिप्त आतंकी समूहों को धन, हथियारों की आपूर्ति इत्यादि को बाधित किया जा सके[1]। भारत को सीमा पार करने को यंत्रीकृत करना होगा। साथ ही नेपाली एजेन्सीयों के साथ सीमा पर गश्त एवं प्रबंधन हेतु सहयोग को उन्नत करना होगा, तभी भारत विरोधी समूह देश की खुली सीमा का दुरूपयोग नहीं कर पायेंगे।
- अधिकांश नेपाली लोगों का मानना है कि बड़ी परियोजनाऐं नेपाल के लिये लाभकारी नहीं हैं। इसलिये जब भारत द्वारा जल संसाधनों के मुद्दों पर सहयोग संबंधी वार्ताऐं की जाती हैं तो इसे नेपालियों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। कई नेपाली विशेषज्ञ भारत–भूटान पनबिजली मॉडल को भारत–नेपाल के संबंध में मुनासिब नहीं समझते हैं। वे चाहते हैं कि नेपाल में उत्पन्न बिजली के लिए भारत को पीक घण्टे की कीमत का भुगतान किया जाये। पनबिजली परियोजना तथा दोनों देशों की सीमा पर स्थित बॉधों के रख रखाव तथा प्रबंधन को केन्द्र सरकार के अधीन विदेशी मामलों के मंत्रालय के अधीन किया जाना चाहिए[15]। इसलिए भारत को नेपाली सरकार और वहॉ के व्यापारियों के साथ–साथ पर्यावरणविदों की राय से नेपाली चिन्ताओं को समझते हुए नई नीति निर्मित करनी चाहिये।
- नेपाल में जारी राजनीतिक गतिरोध का प्रत्यक्ष प्रभाव वहॉ के आर्थिक वातावरण पर परिलक्षित हुआ है। नेपाल में निवेश और रोजगार की महती आवश्यकता है। यद्यपि वहॉ का आर्थिक वातावरण अत्यधिक अनिश्चित है। इसलिये भारतीय व्यापारियों को वहॉ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना कठिन है लेकिन दीर्घकालीन अवधि को ध्यान में रखते हुए, नेपाल में निवेश करना उपयोगी हो सकता है। साथ ही भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक संकट से बाहर निकालने तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिये। नेपाल बिजली की कमी के संकट से जूझ रहा है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु भारत को चाहिए की वह लघु अवधि के लिये नेपाल को बिजली बेचे। यह सामयिक और महत्वपूर्ण मदद होगी।

मोदी की नेपाल यात्रा : संबंधों का नया दौर

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक कारकों की पृष्ठभूमि पर आधारित भारत व नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों में नवीन ऊर्जा व विश्वास का संचार करने हेतु 17 साल पश्चात् किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में मोदी द्वारा अगस्त, 2014 को नेपाल की द्विपक्षीय यात्रा की गई। नेपाल की संविधान सभा को संबोधित करते मोदी ने नेपाल की मदद व विकास के लिए **भ्ज् फार्मूला** अर्थात् **भ. हाईवेज** (राजमार्ग), **प. इन्फॉर्मेशन** वेज (सूचना मार्ग), **ज. ट्रांसवेज** (संचार मार्ग) दिया वहीं भारत द्वारा नेपाल में जारी शांतिप्रक्रिया में हस्तक्षेप संबंधी आशंकाओं को सिरे से नकारते हुए आश्वासन दिया कि 'भारत नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करता है और आशा है की नेपाल में संविधान निर्माण की प्रकिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।'

दोनों देशों के मध्य तीन समझोतों पर हस्ताक्षर किये गए – प्रथम –पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की स्थापना , द्वितीय –नेपाल में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों (प्रमुखत घेंघा रोग) की रोकथाम हेतू आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति के लिए 6.9 करोड नेपाली रूपये की अनुदान सहायता तथा दूरदर्शन व नेपाली टीवी के मध्य सहयोग। इसके अतिरिक्त मोदी ने नेपाल के विकास में भारत के सहयोग की इच्छा को मूर्त रूप प्रदान करते हुए रियायती दर पर द्वारा नेपाल को 1 अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया गया। जिसके पार्श्व में कतिपय महत्वपूर्ण कारण विद्यमान थे **प्रथम,** नेपाल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सम्भावित हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति है जिसका फायदा भविष्य में भारत का मिल सकता है। **द्वितीय,** नेपाल में बढ़ते चीन के प्रभाव के परिसीमन हेतु और **तृतीय** नेपाल अभी संवैधानिक संकट की वजह राजनीतिक व आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है अतः उसे आर्थिक सहायता प्रदान कर आपसी संबंधों में विश्वास बहाली घनिष्ठता बढ़ाना भी हैं।

निष्कर्ष

भारत विरोधी भावना भारत के पड़ौसी देशों में सामान्य परिघटना है। अतः इन गतिविधियों से विचलित होने की बजाय, भारत की नीति नेपाल में दीर्घकालीन, जनकेन्द्रित, आर्थिक क्षमता और मानव संसाधन क्षमता के निर्माण पर आधारित होनी चाहिए। नेपाल में भारत के राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में सहयोग पर आधारित ट्रेक–2 कूटनीति का मॉडल अपनाना होगा। आर्थिक संबंध भी परस्पर लाभ के सिद्धांत पर आधारित हों ताकि नेपाल के लोगों में छोटे राष्ट्र होने की हीनभावना को कम किया जा सके। साथ ही भारत सरकार को नेपाली सरकार व वहॉ की जनता को आश्वस्त करना होगा कि उसे नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली संसद को अपने संबोधन में की और कहा की 'नेपाल सही अर्थों में सम्प्रभू राष्ट्र है और उसमें हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं है लेकिन नेपाल ने जो रास्ता चुना है (लोकतंत्र का) उसमें हम उनको सहयेाग प्रदान करेंगे।' इसके साथ ही नेपाल ने भी भारत को यह आश्वासन दिया कि नेपाली भूमि का प्रयोग किसी भी तरह से भारतीय हितों के खिलाफ नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार भारत द्वारा नेपाल में अभ्युदित नवीन प्रतिमानों के अनुरूप अपनी विदेश नीति को सक्रियता एवं गत्यात्मकता प्रदान करनी होगी ताकि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा एवं राजनीतिक स्थिरता विद्यमान रहे और दोनों देशों के सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता आये। हाल में सुशील कोईराला के नेतृत्व में नई सरकार का गठन नेपाल के संविधान निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, भारत को नेपाल में लड़खड़ाते नवजात लोकतंत्र को सही दिशा व सक्रिय सहयोग प्रदान करना होगा ताकि दक्षिण एशिया क्षेत्र में अवरूद्ध विकास व समृद्धि को गति प्रदान की जा सकें।

वस्तुतः प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा **सहयोग(ब),संपर्क (ब),संस्कृति(ब) और संविधान (ब)** के रूप में **4–ब** पर केन्द्रित थी। इस यात्रा के दौरान मोदी ने नेपाली नागरिकों के दिलों को स्पर्श किया साथ ही सीपीएन माओवादी नेता प्रचंड समेत सभी राजनीतक दलों के नेताओं से मिल कर उनके मन को भी जीत लिया। मोदी द्वारा पहली बार भारत–नेपाल संबंधों में **भू–मनोवैज्ञानिक आयाम** को केन्द्र रखकर वर्षों से नेपाली नागरिकों के मन में भारत के प्रति विद्यमान संशय को दूर करने का प्रयास किया गया। यह संबंधों में नये युग का आगाज है। भविष्य में इसके जारी रहने की पूर्ण आशा है।

संदर्भ सूची

[1]. कौडा, विनय, ''पड़ौस में सरकार का इन्जार'' राजस्थान पत्रिका, जनवरी, 18, 2011, पृष्ठ 8.
[2]. कुमारी, डॉ प्रवेष, 'उभरते लोकतंत्र में संविधान निर्माण की समस्याः नेपाल के संदर्भ में' वर्ल्ड फोकस , नवम्बर 2012 पृष्ठ संख्या–50
[3]. The Hindu, January 29, 2011.
[4]. Murthy Padmaja, "Challenges to India's foreign policy in Nepal", worldfocus, Nov.-Dec., 2010, PP. 605-611.
[5]. www.opendemocracy.net/leena/rikkalatamagnepal.com ,Hindustan 4 June, 2012
[6]. Khannal Elected PM- The Times of India, Feb. 4, 2011.
[7]. Hindustan, 29 August, 2011.
[8]. Hindustan, 28 May, 2011.
[9]. Netindian news networks, India, "Nepal agree to cooprate to fight Terrorism", New Delhi,January 17, 2010 see website http.//netindian.in/news/2010/01/17/000489/india-nepal-agree-cooperate-fight-terrorism.
[10]. Jaiswal pramod, "India-China power game in Nepal & the consequences", Indisute for Defence Study and Analysis (IDSA), New Delhi, Sept. 16, 2010.
[11]. Murthy Padmaja, "Challenges to India's foreign policy in Nepal", worldfocus, Nov.-Dec., 2010, PP. 605-611.
[12]. Gupta Arvind, "India needs a new paradigm in its Nepal policy", Insitute for Defence Study and Analysis, (IDSA), New Delhi, Aug. 18, 2010.
[13]. Nayak Nihar, "Maoists shetoric on India-Nepal relations", Institute for Defence Study and Analysis, (IDSA), New Delhi, January 13, 2010.
[14]. Gupta Arvind, "India needs a new paradigm in its Nepal Policy", Institute for Defence Study and Analyses, (IDSA), New Delhi, August 18, 2010.